सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

इनोवेट. कल्टीवेट. एलीवेट.

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) 2026

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री
राजस्थान

संदेश

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) - 2026 का आयोजन अत्यन्त हर्ष का विषय है। यह मंच कृषि के आधुनिकीकरण, तकनीक-आधारित विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक पहल है।

राजस्थान में कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। वर्तमान समय में, जब हम जलवायु परिवर्तन, संसाधनों के कुशल उपयोग और वैश्विक बाजार से जुड़ाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब नवाचार, स्थिरता और समावेशिता को अपनाना समय की आवश्यकता बन चुका है।

GRAM-2026 एक ऐसा मंच है, जो संवाद को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित करने और किसानों, एग्री-बिजनेस, शोधकर्ताओं तथा नीति-निर्माताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है। यह आयोजन किसानों को सशक्त बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और कृषि निर्यात एवं मूल्य संवर्धन के नए अवसर सृजित करने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा।

राजस्थान सरकार, कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। डिजिटल कृषि, जल संरक्षण और उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन देने जैसी महत्त्वपूर्ण पहलों के माध्यम से हम राजस्थान को सतत् कृषि पद्धतियों में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखते हैं।

मैं सभी हितधारकों से इस परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल होने और एक सशक्त, नवाचारी एवं भविष्य के लिए तैयार कृषि क्षेत्र के निर्माण में योगदान देने का आह्वान करता हूँ।

(भजनलाल शर्मा)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
मंत्री

सत्यमेव जयते

कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा
जन अभियोग निराकरण विभाग
राजस्थान सरकार

संदेश

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) 2026 में पधारे आप सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।

यह आयोजन राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें हम कृषि को एक गतिशील, तकनीक-आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

राजस्थान में कृषि एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जो **नवाचार, स्थिरता और निवेश-आधारित विकास** पर केन्द्रित हैं। बदलती वैश्विक खाद्य प्रणालियों और जलवायु-स्मार्ट समाधानों की बढ़ती आवश्यकताओं के मध्य हमारा प्रदेश एग्रीबिजनेस, एग्री-टेक और वैल्यू-एडेड उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। GRAM एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है, जो निवेशकों, नवप्रवर्तकों और किसानों को जोड़ता है तथा मज़बूत साझेदारी को बढ़ावा देता है। यह मंच ऐसे अवसरों का सृजन करता है, जो न केवल कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाते हैं, अपितु उसके भविष्य को भी नवीन दिशा प्रदान करते हैं।

राजस्थान सरकार कृषि निवेश, निर्यात-उन्मुख उत्पादन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विशेष ध्यान मोटे अनाज (मिलेट्स), बागवानी, प्रिसिजन फार्मिंग और जल-संरक्षण तकनीकों पर है, जो राजस्थान को सतत् कृषि और वैश्विक कृषि व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक हैं।

मैं उद्योग जगत के प्रमुखजनों, निवेशकों और उद्यमियों को आमंत्रित करता हूँ कि वे राजस्थान के कृषि के क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं का लाभ उठाएं। आइए, हम सभी मिलकर एक ऐसा भविष्य का निर्माण करें जहाँ कृषि केवल आजीविका का साधन ही नहीं, अपितु आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सशक्त आधार बने।

(डॉ. किरोड़ी लाल)

अनुक्रमणिका

एक नज़र में राजस्थान 02

- आर्थिक परिदृश्य - राजस्थान 03
- राजस्थान: अवसरों की भूमि 04

एक नज़र में - राजस्थान का कृषि क्षेत्र 06

- मुख्य उत्पादन आँकड़े 07
- उद्यानिकी क्षेत्र में प्रमुख क्षमताएँ 07
- कृषि इनपुट 08
- जैविक खेती 08
- प्लास्टिकल्चर तकनीकें 08
- कृषि मशीनीकरण 08
- सिंचाई 09
- संरक्षित खेती 09
- पशुपालन 10
- कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी पहल 13
- कटाई उपरांत प्रबंध प्रणाली 13

निवेश के अवसर – इंफ्रास्ट्रक्चर 15

- प्रेशर सिंचाई 15
- सोलर पंप 15
- कृषि उपकरणों की किराये पर उपलब्धता 17
- फार्म मशीनीकरण 17
- निर्यात-उन्मुख कृषि उत्पाद 17
- मत्स्य पालन 17
- अनुबंध खेती 17
- जैविक खेती 17

निवेश के अवसर – कृषि और संबद्ध क्षेत्र 18

- अनाज 18
- तिलहन 19
- दालें 20

- फल व सब्जियां 21
- बीज मसाले 22
- अन्य 23
- औषधीय/हर्बल 23
- रेडी-टू-कुक (RTC), रेडी-टू-ईट (RTE) 24
- वन उत्पाद 24

5. अन्य अवसर 24

- कृषि-इनपुट 24
- परिवहन एवं आपूर्ति श्रृंखला 24
- डेयरी 25
- ऊन 25
- विपणन और मंडी सुविधा 25

6. निवेश अनुकूल नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र 26

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए नीति की प्रमुख विशेषताएँ 27

7. विज़न 2047 28

- प्रमुख क्षेत्र 28
- प्रगति का बीजारोपण 29

8. ग्राम 2026 30

- ग्राम के उद्देश्य 31
- ग्राम 2026 - एक नज़र में 32
    - प्रदर्शनी 32
    - सम्मेलन 32
    - प्रस्तुतियाँ और पैनल चर्चाएँ 33
    - इवेंट की मुख्य बातें 34
    - किसे भाग लेना चाहिए 35
    - ग्राम 2026 में क्यों शामिल हों? 35

9. प्रमुख सम्पर्क 36

1. एक नज़र में राजस्थान

राजस्थान को "वीरों, पराक्रम की भूमि" के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सीमा उत्तर में पंजाब, उत्तर-पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से लगती है।

राजस्थान में भारत की 14.14% कृषि योग्य भूमि है, जो 25.5 मिलियन हेक्टेयर है।

2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 68.5 मिलियन थी और मार्च 2024 तक इसके 83.3 मिलियन होने का अनुमान है।

राज्य में एक मजबूत कृषि आधार है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर, देश के सभी प्रमुख शहरों से बेहतरीन रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो लगभग 3,42,239 वर्ग किमी (34 मिलियन हेक्टेयर) में फैला हुआ है।

अनुमानित जनसंख्या
~83.3 मिलियन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)
₹18.75 लाख करोड़
(वर्तमान मूल्य पर)

प्रति व्यक्ति आय
~₹2.02 लाख

राजस्थान में भूमि उपयोग पैटर्न प्रतिशत

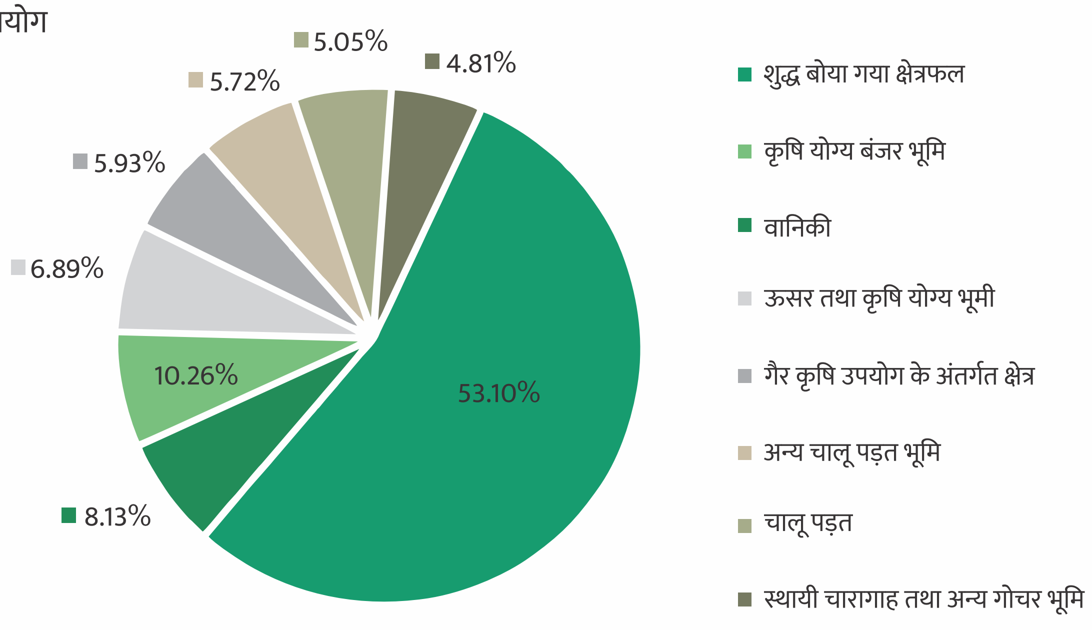

आर्थिक परिदृश्य - राजस्थान

26.92%

2024-25 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का राज्य के सकल मूल्य संवर्धन (Gross State Value Added) में कुल योगदान रहा है। यह 18% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

~27%

आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है, या तो किसान के रूप में या कृषि मजदूर के रूप में।

~62%

के लगभग आबादी कृषि क्षेत्र से संबंधित है।

2.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर

का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019 से 2024 के बीच राजस्थान ने आकर्षित किया।

~11.25% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate) ने 2024-25 के दौरान लगभग 11.25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की, जो इसी अवधि में भारत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विकास दर से 10.47% अधिक है।

₹ 2.02 लाख

राज्य की प्रति व्यक्ति आय (2024-25) है।

GSVA की क्षेत्रीय संरचना (2024–25 अनुमान)

कुल GSVA% लगभग ₹15.7 लाख करोड़

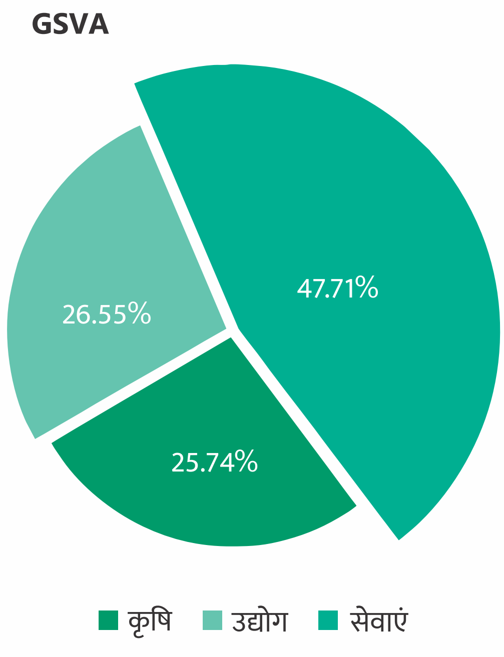

राजस्थान:
अवसरों की भूमि

प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों से निकटता

भारत के पांच प्रमुख राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है, जिससे एक विशाल कंज्यूमर मार्केट तक पहुंच मिलती है।

मजबूत एवं व्यापक परिवहन संपर्क

देश में नेशनल हाईवे का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, जिसकी कुल सड़क लंबाई 7,310 किमी से ज़्यादा है। डीएमआईसी का 39% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है।

कृषि प्रधान राज्य

कृषि का मजबूत सांस्कृतिक महत्व और फसलों की उच्च विविधता राजस्थान को भारत के कृषि राज्यों में सबसे आगे रखती है।

भूमि की उपलब्धता

जैविक खेती, अनुबंध खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) तथा कटाई उपरांत अवसंरचना (पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए व्यापक अवसर प्रदान करती है।

निर्यात की अपार क्षमता

मसालों और अन्य कृषि उत्पादों का महत्वपूर्ण और बढ़ता निर्यात, जो भारत के कृषि निर्यात में सार्थक योगदान देता है।

सरकारी प्रोत्साहन

निर्यात-उन्मुख कृषि और खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयों, जिसमें मसाले, फल और सब्जियां शामिल हैं, पर आकर्षक प्रोत्साहन और सब्सिडी।

रणनीतिक स्थान

देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों के बीच एक प्राकृतिक गलियारा, जो इसे एक महत्वपूर्ण व्यापार और वाणिज्य केंद्र बनाता है।

मजबूत औद्योगिक अवसंरचना

कृषि-आधारित उद्योगों के विकास के लिए 39 मेगा फूड पार्कों की घोषणाए जिनमें भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में 2 प्रमुख फूड पार्क शामिल हैं, जो मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में सहायक हैं।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस

निवेश आवेदनों को जमा करने, ट्रैक करने और समयबद्ध क्लीयरेंस के लिए ऑनलाइन सिंगल-विंडो सिस्टम।

- DPIIT के LEADS 2024 के अनुसार, राजस्थान को लैंडलॉक्ड क्लस्टर में फास्ट मूवर के रूप में रैंक किया गया।
- राज्य देश में खनिज उत्पादन में तीसरे स्थान पर रहा और कुल खनिज उत्पादन में 14.7% का योगदान दिया।
- राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
- 2030 तक भारत के 450 GW नवीकरणीय विज़न को शक्ति प्रदान करना।
- 360+ से ज़्यादा अच्छी तरह से विकसित औद्योगिक क्षेत्र। विशिष्ट उद्योगों के लिए कस्टम-निर्मित औद्योगिक पार्क।
- एग्रो-प्रोसेसिंग सेक्टर एक प्रमुख उद्योग है।

2. एक नज़र में - राजस्थान का कृषि क्षेत्र

राजस्थान, 270.86 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के साथ विविध फसल और पशुधन उत्पादन में अग्रणी है। 83% कृषि वर्षा पर निर्भर है, जो सीमित जल संसाधनों और क्षरित भूमि के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। राज्य में 568 लाख पशुधन और 42,000 से अधिक सहकारी समितियाँ किसानों की सहायता करती है। एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन, चारागाह विकास और कृषि प्रसंस्करण स्थायी ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

10
कृषि-जलवायु क्षेत्र

53%
शुद्ध बोया गया क्षेत्र

वर्ष 2024-2025
के दौरान उत्पादित शीर्ष कृषि वस्तुएँ (लाख टन)

खाद्यान्न
283.98

कुल तिलहन
100.46

दालें
47.13

मुख्य उत्पादन आँकड़े

राजस्थान इनके उत्पादन में

#1 बाजरा, सरसों, कुल तिलहन, मोटे अनाज ग्वार

#2 मूँगफली, दुग्ध उत्पादन

#3 चना, कुल दालें, सोयाबीन

राष्ट्रीय योगदान

88.8%
भारत का ग्वार राजस्थान में उत्पादित होता है

47.5%
भारत का ऊन

14.5%
भारत का दूध

राजस्थान में

- भारत का 80% इसबगोल
- भारत का 61% जौ
- भारत का 89% ग्वार पैदा होता है

राजस्थान का स्थान (उत्पादन)

- मूंगफली में दूसरा
- चना, कुल दालें एवं सोयाबीन में तीसरा
- ज्वार, कपास एवं कुल खाद्यान्न में चैथा
- गेहूं में पांचवां

उद्यानिकी क्षेत्र में प्रमुख क्षमताएँ

- राजस्थान अनार, जैतून, खजूर और जोजोबा के लिए खेती की नई तकनीकों को अपनाने में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।
- राजस्थान 28 सरकारी बागवानी नर्सरी के मज़बूत नेटवर्क के साथ एक मज़बूत बागवानी राज्य बनकर उभरा है। हाई-टेक नर्सरी अच्छी क्वालिटी के फलों के पौधों और छोटे पौधों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में मदद करती हैं।

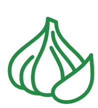

लहसुन का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक

खट्टे फलों का अग्रणी उत्पादक

अनार का बड़ा उत्पादक

1473 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ एलोवेरा का प्रमुख उत्पादक

कृषि इनपुट

- राजस्थान में मक्का, गेहूँ, सरसों, चना, जौ और सोयाबीन, ग्वार, मूंगफली और अरंडी जैसी नकदी फसलों की अधिक उत्पादक किस्में उगाई जाती हैं।
- राजस्थान में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की कंपनियाँ किसानों को बीज और उर्वरकों की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं।
- राजस्थान खेत की फसलों के बीजों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

कृषि मशीनीकरण

- राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सीमांत/लघु , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषकों को कृषि यंत्र क्रय करने पर 50 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी के कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- कृषकों को महंगे कृषि यंत्र बाजार दर से कम दर पर किराये पर उपलब्ध कराए जाने हेतु कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाती है।
- ग्राम सेवा सहकारी समिति/ क्लस्टर लेवल फेडरेशन/कृषक उत्पादक संगठनों को 80 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 24 लाख) एवं ग्रामीण उद्यमी/प्रगतिशील कृषक को 40 प्रतिशत (अधिकत्तम 12 लाख) का अनुदान दिया जाता है । राज्य में अब तक 2,185 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है।

प्लास्टिकल्चर तकनीकें

इसमें खेती के लिए प्लास्टिक का उपयोग करके कृषि/बागवानी शामिल है

- मुख्य उपयोग- ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर सिंचाई, पॉलीहाउस
- क्षेत्र कवरेज- ड्रिप सिंचाई क्षेत्र: 6.76 लाख हेक्टेयर, स्प्रिंकलर सिंचाई क्षेत्र: 18.28 लाख हेक्टेयर

50-60%
उपज में वृद्धि

60-70%
पानी की बचत

30-40%
उर्वरक की बचत

खरपतवार की
वृद्धि में कमी

जैविक खेती

- वर्ष 2024-25 में राजस्थान भारत में प्रमाणित जैविक खेती क्षेत्र के मामले में तीसरे स्थान पर है, जहाँ APEDA (NPOP) के अनुसार कुल प्रमाणित (Organic + Inconversion) क्षेत्र लगभग 5.52 लाख हेक्टेयर है।

संरक्षित खेती

- राजस्थान में संरक्षित खेती क्लस्टर में शामिल हैं:
    - पॉलीहाउस- 1.16 करोड़ वर्ग मीटर
    - शेडनेट हाउस- 40 लाख वर्ग मीटर
- उगाई जाने वाली मुख्य फसलें-
    - खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, स्ट्रॉबेरी
    - जरबेरा और डच रोज़ आमतौर पर उगाए जाने वाले फूलों की किस्में हैं
- फोकस जिले- जयपुर, अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर
- शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए संरक्षित खेती राजस्थान में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

सिंचाई

- राजस्थान में लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत आता है।
- राजस्थान में 2023-24 के अनुसार सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कुएँ/ट्यूबवेल (~66%) हैं। नहरें दूसरा सबसे बड़ा स्रोत हैं और उनसे लगभग 30% सिंचाई होती है। तालाबों से ~0.6–1% तथा अन्य छोटे स्रोतों से ~0.3–2% सिंचाई होती है।
- राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि, सिंचाई परियोजनाएँ, नई योजनाएँ और लक्ष्य (जैसे RAM जल सेतु लिंक, सिंचाई जल ग्रिड मिशन आदि) दिए गए हैं।
- बाढ़ सिंचाई के विकल्प के रूप में दबाव सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है: दबाव सिंचाई प्रणालियों के लिए कमांड क्षेत्र- इंदिरा गांधी नहर, चंबल नर्मदा, जवाई बिसलपुर और बांसवाड़ा में माही।

पशुपालन

- राजस्थान लगभग 56.8 मिलियन पशुधन आबादी के साथ देश में दूसरे स्थान पर है और भारत की कुल पशुधन आबादी का 10% से अधिक हिस्सा रखता है।
- बकरी की आबादी में 14% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है।
- राजस्थान में सभी प्रमुख पशुधन श्रेणियों में हाल के वर्षों में मज़बूत वृद्धि दर्ज की गई है।

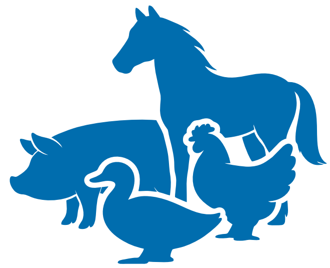

2nd
पशुधन संख्या

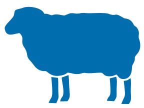

1st
भेड़ एवं बकरियों की संख्या

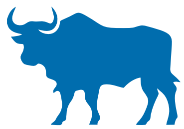

2nd
भैंस संख्या

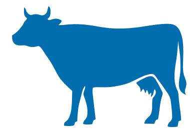

5th
मवेशियों की संख्या

पशुधन की श्रेणियाँ 2019 की पशु गणना अनुसार

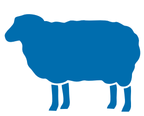

भेड़: 2,12,739
(देश का 10.64%)

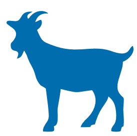

बकरियां: 2.08 करोड़
(देश का 14.00%)

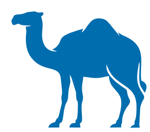

ऊंट: 0.79 करोड़
(देश का 85.09%)

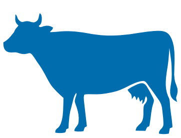

मवेशी (गोवंश): 1.39 करोड़
(देश का 7.20%)

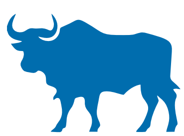

भैंस: 1.37 करोड़
(देश का 12.50%)

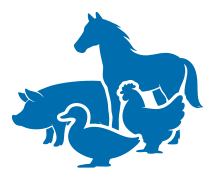

अन्य: 2,13,000

डेयरी

- राजस्थान भारत में दूध उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है, और भारत में पशुओं की आबादी के मामले में 5वें स्थान पर है।
- राजस्थान भारत में दूध का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है (34.73 मिलियन टन) और भारत के कुल दूध उत्पादन में 14.44% का योगदान देता है।
- गिर, थारपारकर, राठी और साहीवाल सबसे अच्छी दूध देने वाली देषी मवेशियों की नस्लें हैं। नागोरी बैल एक प्रमुख भार ढोने वाली नस्ल है।
- भैंसों की आबादी के मामले में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। भैंसें दूध उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देती हैं, उसके बाद क्रमशः गायें और बकरियां आती हैं।
- दूध की खरीद और मार्केटिंग को राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ़) के तहत डेयरी सहकारी समितियों के एक मजबूत नेटवर्क द्वारा सपोर्ट किया जाता है। राज्य भर में लगभग 13,878 डेयरी सहकारी समितियां काम कर रही हैं।
- राजस्थान का बड़ा दूध उत्पादन दूध प्रोसेसिंग प्लांट और कमर्शियल डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

ऊन

- सालाना 15 मिलियन किलोग्राम से अधिक ऊन उत्पादन के साथ, राजस्थान भारत में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है, जो राष्ट्रीय ऊन उत्पादन में 47.98% से अधिक का योगदान देता है।
- राज्य में आठ अलग-अलग भेड़ की नस्लें हैं जो उच्च गुणवत्ता वाली कालीन ऊन के लिए जानी जाती हैं, और उत्पादित ऊन का 85% कालीन ग्रेड का होता है।
- राजस्थान में लगभग 70 ऊन प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रही हैं।

पोल्ट्री एवं मटन

- राजस्थान में पोल्ट्री की आबादी पिछले दो जनगणनाओं के बीच 60% से अधिक तेजी से बढ़ी है, जो 2019 में लगभग 14.6 मिलियन तक पहुंच गई है।
- पशुपालन विभाग ट्रेनिंग और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च उत्पादन देने वाली लेयर और ब्रॉयलर नस्लों को बढ़ावा दे रहा है।
- प्रताप धन, राजस्थान में विकसित एक नस्ल, पारंपरिक देसी पक्षियों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक अंडे देती है, जबकि कड़कनाथ जैसी नस्लों को प्रीमियम खास बाजारों के लिए लोकप्रिय बनाया जा रहा है।
- इन विकास कार्यक्रमों और ट्रेनिंग ने प्रजनकों को पोल्ट्री और छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के क्षेत्रों में लगातार उच्च वृद्धि हासिल करने में मदद की है।

मत्स्य पालन

- राजस्थान में मीठे पानी और खारे पानी दोनों के संसाधन उपलब्ध हैं।
- इसमें लगभग 430 हजार हेक्टेयर मीठे पानी का क्षेत्र है, इसके अलावा 30 हजार हेक्टेयर नदियां और नहरें, 80 हजार हेक्टेयर जलभराव वाले क्षेत्र और 180 हजार हेक्टेयर खारे पानी से प्रभावित क्षेत्र हैं जब टैंक पूरी तरह से भरे होते हैं।
- राजस्थान में मछली उत्पादन 12% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय औसत (8%) से अधिक है।

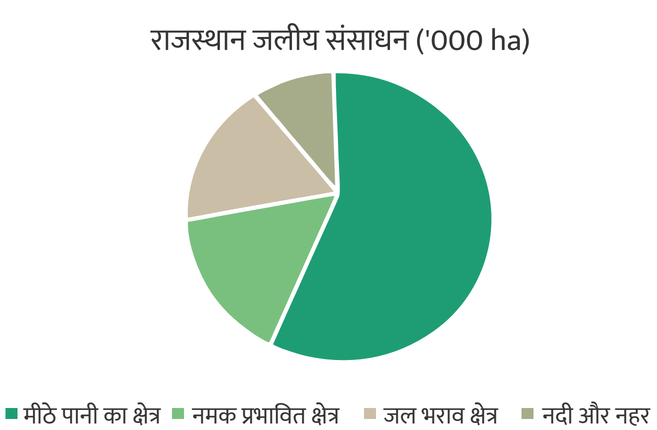

राजस्थान में पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या और उनके प्रमुख प्रकार

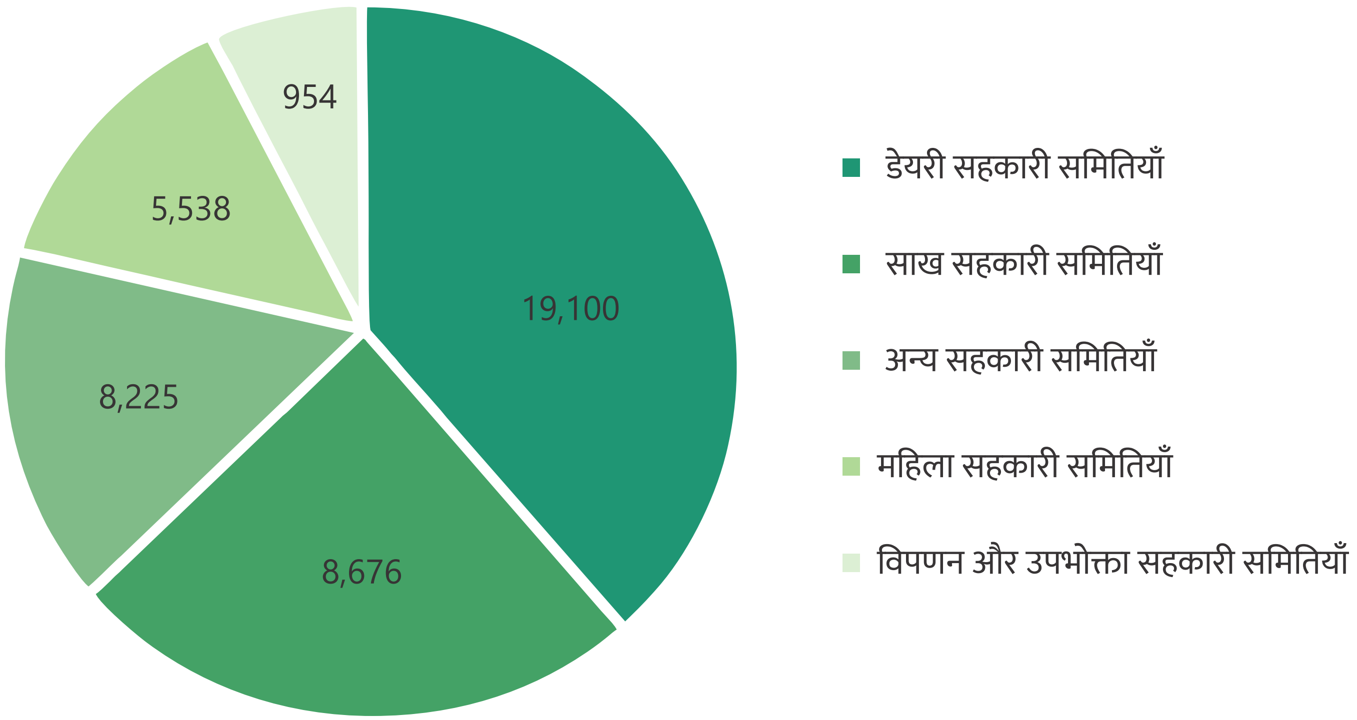

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी पहल

राजस्थान में प्रोसेस्ड फूड उद्योग विकास के लिए तैयार है। राज्य की अनुकूल कृषि स्थितियाँ और मुख्य फसलों का मज़बूत उत्पादन इस इंडस्ट्री के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। राजस्थान सरकार मज़बूत फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट की ज़रूरत को समझती हैः

- राज्य भर में कई एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रही हैं, जो प्राथमिक फसलों और बागवानी उत्पादों को संभालती हैं।
- राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 (जिसे 2025 तक के लिए प्रभावी माना जा रहा है) का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। यह नीति एग्रो-प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान, ब्याज सब्सिडी और भाड़ा सहायता प्रदान करती है।
- दो कृषि निर्यात क्षेत्र चालू हैं (धनिया और जीरा पर ध्यान केंद्रित करते हुए) और पाँच जिलों को कवर करते हैं।
- विशिष्ट कमोडिटी बाजारों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें रामगंजमंडी (धनिया के लिए), और जोधपुर और मेड़ता (जीरा के लिए) शामिल हैं।

कटाई-उपरांत प्रबंधन प्रणाली

- कोल्ड चेनः MoFPI द्वारा 'कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर योजना' के तहत चार कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से अलवर में सुविधा चालू है।
- ऑनलाइन मंडियाँः 173 कृषि उपज मंडी समितियों को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) के साथ एकीकृत किया गया।
- यह ई-प्लेटफ़ॉर्म किसानों को बिचैलियों को हटाकर सीधे बाजार में अपनी उपज बेचने में मदद करता है।
- यह पहल सीधे व्यापार और अधिक पारदर्शिता को सक्षम बनाती है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों को ऑनलाइन बेहतर कीमतें और बाजार तक पहुँचने में मदद मिलती है।

भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क

भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क

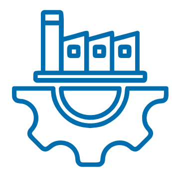

360 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र और विशिष्ट सेक्टर पार्क

व्यापक नहर और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ

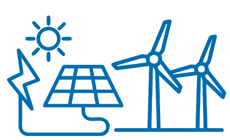

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी

3. निवेश के अवसर - इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रेशर सिंचाई

- राजस्थान ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी कुशल प्रणालियों के तहत सिंचित क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा रहा है, जिसका लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में पारंपरिक बाढ़ सिंचाई से महत्वपूर्ण बदलाव करना है, जिससे आधुनिक उपकरणों की मांग पैदा होती है।
- यह पाइप, पंप, फिल्टर और ऑटोमेशन समाधान सहित प्रेशर सिंचाई प्रणालियों के निर्माण, असेंबली और सर्विसिंग के लिए आकर्षक अवसर खोलता है।

सोलर पंप

- पृथ्वी पर कुछ उच्चतम सौर विकिरण स्तरों और सालाना 325 से अधिक धूप वाले दिनों के साथ, राजस्थान खेत में ऊर्जा की जरूरतों को मज़बूती से पूरा करने के लिए सौर-आधारित सिंचाई को प्राथमिकता दे रहा है।
- PM-KUSUM और समर्पित सोलर पंप कार्यक्रमों जैसी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएँ महत्वपूर्ण पूंजी सब्सिडी प्रदान करती हैं, जिससे यह तेजी से बढ़ते कृषि उपयोगकर्ताओं के लिए 1.67 लाख सोलर पंप निर्माण, स्थापना और प्रभावी संचालन एवं प्रबंधन सेवाओं में निवेश करने का एक उपयुक्त समय है।

कृषि उपकरणों की किराये पर उपलब्धता

- इंसानी और जानवरों की ताकत पर निर्भरता कम करने के लिए, राज्य छोटे और सीमांत किसानों को मशीनीकरण में मदद करता है, जो अकेले मशीनें नहीं खरीद सकते।
- जिलों में कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHC) स्थापित करने की व्यापक संभावनाएँ हैं, जिनके माध्यम से ट्रैक्टर, कृषि उपकरण एवं विशेष मशीनरी किराये पर उपलब्ध कराई जा सकती है। यह व्यवस्था संस्थागत ऋण (Institutional Credit) और सरकारी सहयोग द्वारा समर्थित होगी।

फार्म मशीनीकरण

राज्य फसल चक्र के प्रत्येक चरण में दक्षता बढ़ाने और श्रम आवश्यकताओं को कम करने के लिए आधुनिक कृषि मशीनरी को अपनाने को प्रोत्साहित कर रहा है। निम्नलिखित उपकरणों में निवेश लाभकारी है।

- भूमि की तैयारी (जुताई, लेजर लेवलिंग)
- बीज बुवाई एवं रोपण
- उर्वरक एवं कीटनाशक का सटीक अनुप्रयोग
- कटाई एवं थ्रेशिंग
- कटाई उपरांत प्रबंधन एवं हैंडलिंग
- ग्रेडिंग, पैकेजिंग और परिवहन से जुड़ी मशीनरी

निर्यात-उन्मुख कृषि उत्पाद

राजस्थान में किन्नू, मैंडरिन, ताज़ी सब्जियाँ, आँवला और उसके उत्पाद, मसाले, बीज मसाले, जड़ी-बूटियाँ, शहद और उसके उत्पाद, लहसुन (साबुत और पाउडर), गुलाब का तेल, सूखी पंखुड़ियाँ, गुलकंद, इसबगोल की भूसी, सेना और बॉडी ग्रेड मेहंदी सहित कई तरह की फसलों और उत्पादों में निर्यात की क्षमता है।

मत्स्य पालन

राजस्थान के कई जल निकाय और जलाशय अंतर्देशीय और संस्कृति मत्स्य पालन के विस्तार के लिए अवसर प्रदान करते हैं। कुछ जलाशयों में उत्पादकता 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक होने के कारण, घरेलू और संस्थागत बाज़ारों के लिए बीज उत्पादन, फ़ीड आपूर्ति, ग्रो-आउट खेती, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण में अवसर मौजूद हैं।

अनुबंध खेती

- राजस्थान कृषि उपज बाजार अधिनियम में संशोधन, जिसमें तीसरे संशोधन के माध्यम से पेश किए गए प्रावधान शामिल हैं, उत्पादकों और खरीदारों के बीच अनुबंध खेती की व्यवस्था को कानूनी रूप से सक्षम बनाते हैं।
- यह ढाँचा माल्ट जौ, फल, सब्जियाँ, औषधीय और सुगंधित पौधों जैसी फसलों में दीर्घकालिक साझेदारी का समर्थन करता है, जो इनपुट आपूर्ति, विस्तार सेवाओं, बाय-बैक व्यवस्था और मूल्य श्रृंखला बुनियादी ढाँचे में निवेश की क्षमता प्रदान करता है।

जैविक खेती

- राजस्थान के बड़े हिस्से में स्वाभाविक रूप से रासायनिक उपयोग कम होता है, जो जैविक खेती के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करता है, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों को जैविक समूहों के रूप में अधिसूचित या बढ़ावा दिया जाता है।
- सरकार सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती का समर्थन करती है, जिससे जैविक फसल उत्पादों के विकास और विपणन तथा प्राकृतिक कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात के अवसर पैदा होते हैं।

4. निवेश के अवसर - कृषि और संबद्ध क्षेत्र

अनाज

उत्पादन	अवसर	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र/जिले	मुख्य बाज़ार स्त्रोत
मक्का	मक्का आधारित प्रसंस्करण संयंत्र जिसमें स्टार्च संयंत्र, कॉर्न सिरप तैयार करना, विभिन्न एंजाइम तैयारी शामिल हो सकती है	उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़	उदयपुर, भीलवाड़ा, निंबाहेड़ा, बेगू, खेरली, इडलेरा
जौ	माल्ट और फूड एडिटिव्स निर्माण/तैयारी इकाइयाँ	अजमेर, जयपुर, सीकर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा	जयपुर, चोमू, सीकर, श्री माधोपुर, श्री गंगानगर, पदमपुर, श्री करणपुर
गेहूं	आटा मिलें और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद इकाइयाँ	श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा	कोटा, बारां, बूंदी, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़
बाजरा	पोल्ट्री/पशु आहार, माल्ट इकाइयां, सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग इकाइयाँ	बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनूं	अलवर, खैरथल, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, हिंडौन, जयपुर

तिलहन

उत्पादन	अवसर	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र/जिले	मुख्य बाज़ार स्त्रोत
सोयाबीन	सोया मिल्क और सोया-प्रोटीन आइसोलेट्स के लिए सोया बेस्ड फूड प्रोसेसिंग प्लांट	झालावाड़, बारां, कोटा, प्रतापगढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़	कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़
सरसों	सरसों का तेल निकालने का प्लांट, रिफाइनरी, सरसों की चटनी आदि	अलवर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़	अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और कोटा, श्रीगंगानगर के सभी मार्केट
तिल	छिलका हटाने वाली इकाइयाँ	पाली, टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा	हिंडौन, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, जोधपुर, भीलवाड़ा
जैतून	जैतून तेल, चाय, पत्तियों का अर्क	बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर	श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर
मूंगफली	भुनी हुई मूंगफली, मूंगफली का मक्खन	बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, चुरू, श्री गंगानगर	बीकानेर, लूणकरणसर, जयपुर, चोमू

दालें

उत्पादन	अवसर	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र/जिले	मुख्य बाज़ार स्त्रोत
मूंग	दालों के प्रसंस्करण (स्प्लिटिंग), पापड़ तथा अन्य मूल्य-संवर्धित उत्पादों की इकाइयाँ	पाली, नागौर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जालौर	मेडता, नागौर, सुमेरपुर, जोधपुर, केकड़ी, किशनगढ़ (अजमेर)
मोठ	नमकीन भुजिया और दाल से बने प्रोडक्ट्स	चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर	नोखा, लूणकरणसर, सरदारशहर (चूरू), बाड़मेर
चना	बेसन और दूसरे वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स	चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, टोंक	बीकानेर, जैसलमेर, मेरटा, जयपुर, केकड़ी, किशनगढ़ (अजमेर)
उड़द	दालों के प्रसंस्करण (स्प्लिटिंग) तथा अन्य उत्पादों की इकाइयाँ	भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा	बीकानेर, लूणकरणसर, जयपुर, चोमू

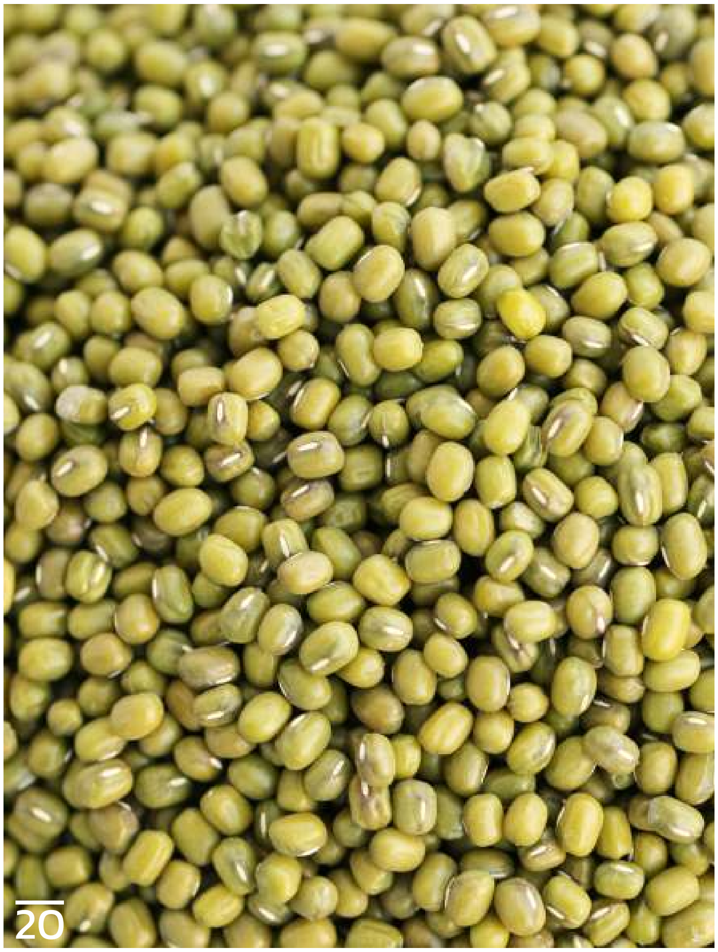

फल व सब्जियां

उत्पादन	अवसर	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र/जिले	मुख्य बाज़ार स्त्रोत
आलू	प्रसंस्करण संयंत्र जिसमें चिप्स, पाउडर शामिल हैं	भरतपुर, धौलपुर	भरतपुर, धौलपुर, जयपुर
टमाटर	टमाटर आधारित मूल्य संवर्धित उत्पादों के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ, जिनमें फ्लेवर एवं सामग्री (इंग्रीडिएंट्स), रेडी टू यूज सॉस, पाउडर, प्यूरी, पेस्ट, साल्सा, पिज्जा सॉस, केचप और जूस शामिल हैं।	जयपुर, सिरोही, अजमेर, दौसा, टोंक	जयपुर, चोमू, बस्सी, रेवदर (सिरोही)
प्याज	सर्दियों के लिए प्याज के टुकड़े/पाउडर का उत्पादन करने के लिए	सीकर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर और अलवर- ग्रीष्मकालीन फसल के लिए	सीकर, जयपुर, चोमू, फलोदी; शीतकालीन फसल के लिए अलवर और खैरथल
लहसुन	लहसुन के टुकड़े/पाउडर	बारां, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़	भवानी मंडी, झालरापाटन
संतरा	एसेप्टिक फलों के जूस, फलों के कंसंट्रेट तथा पाउडर की प्रसंस्करण इकाइयाँ	झालावाड़	जयपुर, जोधपुर
अनार	एसेप्टिक (सड़न रोकने वाला) फलों का रस, सांद्र और अन्य मूल्य वर्धित उत्पाद इकाइयाँ	जालौर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और श्री गंगानगर	सवाई माधोपुर, जयपुर
अमरूद	एसेप्टिक फलों के जूस, फलों के कंसंट्रेट इकाइयाँ	सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर	श्री गंगानगर
किन्नू	एसेप्टिक फलों के जूस, फलों के कंसंट्रेट इकाइयाँ	श्री गंगानगर और हनुमानगढ़	श्री गंगानगर
खजूर	छुआरा, सिरका, अचार, जूस, स्टार्च, एसेंस, मिष्ठान्न, शराब, पोल्ट्री चारा, आदि	बीकानेर और जैसलमेर	बीकानेर और जैसलमेर

बीज मसाले

उत्पादन	अवसर	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र/जिले	मुख्य बाज़ार स्त्रोत
जीरा	सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और प्राकृतिक अर्क इकाइयाँ	बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली	बाड़मेर
धनिया	सफाई, ग्रेडिंग, पाउडरिंग, पैकिंग और प्राकृतिक अर्क इकाइयाँ	झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ और बूंदी	रामगंज मंडी, कोटा, बारां
मेथी	सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और प्राकृतिक अर्क इकाइयाँ	बीकानेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर	कोटा, जयपुर
अजवायन	सफाई, ग्रेडिंग, और पैकिंग इकाइयाँ	चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़	भीलवाड़ा, जयपुर
सौंफ	सफाई, ग्रेडिंग, और पैकिंग इकाइयाँइकाइयाँ	नागौर, जोधपुर, पाली, टोंक, सिरोही	लालसोट, निवाई

अन्य

उत्पादन	अवसर	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र/जिले	मुख्य बाज़ार स्त्रोत
ग्वार	प्रसंस्करण इकाइयाँ जिनमें विभाजित और पाउडर संयंत्र शामिल हो सकते हैं; कागज, कपड़ा, खनन में ग्वार गम डेरिवेटिव और भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स में ग्वार गम पाउडर	बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, सीकर, श्री गंगानगर	बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़
कपास	जिनर्स, स्पिनर्स और कपड़ा इकाइयों में कपास प्रसंस्करण इकाइयाँ	श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर	श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर

औषधीय/हर्बल

उत्पादन	अवसर	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र/जिले	मुख्य बाजार स्त्रोत
ईसबगोल	ईसबगोल की भूसी, पाउडर आदि के लिए ईसबगोल प्रसंस्करण सुविधाएं	बाड़मेर, जालौर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़	मेड़ता, नागौर, निम्बाहेड़ा, बाड़मेर
हर्बल औषधि	हर्बल औषधि ईसबगोल, सोनामुखी, आंवला, एलोवेरा, अश्वगंधा, मेंहदी आदि पर आधारित हर्बल औषधियों की प्रसंस्करण इकाइयाँ	आंवलाः जयपुर, अजमेर, सीकर जिले ईसबगोलः बाड़मेर, जालौर, जोधपुर सोनामुखीः जोधपुर, फलोदी मेहंदी: सोजत एलोवेराः चूरू, भरतपुर	आंवलाः चोमू, जयपुर सोनामुखीः फलोदी मेहंदी: सोजत
मेहंदी	हेयर-डाई ग्रेड मेहंदी प्रसंस्करण के लिए उच्च क्षमता	पाली	सोजत

रेडी-टू-कुक (आरटीसी) रेडी-टू-ईट (आरटीई) और पैक्ड फूड

बदलती आबादी, बढ़ते शहरीकरण, और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी राजस्थान में 9.88% की (CAGR) साथ ही वर्कफोर्स में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी (राष्ट्रीय स्तर पर 45% की तुलना में 54%), राज्य में RTC&RTE और पैक्ड फूड मार्केट के तेज़ी से विस्तार को बढ़ावा दे रहे हैं।

दिल्ली-एन.सी.आर. और उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों के प्रमुख बाज़ारों से राज्य की निकटता के कारण बाज़ार तक तेजी से पहुंच संभव हो पाती है और लॉजिस्टक्स लागत कम हो जाती है।

बड़ी FMCG कंपनियों ने पहले ही राज्य में फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित कर ली हैं, ताकि वे इसके बड़े कंज्यूमर बेस और कच्चे माल तक पहुंच का फायदा उठा सकें।

वन उत्पाद

उत्पादन	अवसर	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र/जिले	मुख्य बाज़ार स्त्रोत
महुवा, शहद, लाख, बांस आदि	प्रसंस्करण इकाइयाँ	मेवाड़ क्षेत्र, झालावाड़ और भरतपुर	उदयपुर, प्रतापगढ़

5. अन्य अवसर

कृषि-इनपुट

- बीज अनुसंधान और विकास इकाइयाँ।
- फसल प्रौद्योगिकी और कृषि-रसायन।
- सिंचाई प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म-सिंचाई प्रणालियाँ।
- जैविक और जैव-उर्वरक इनपुट।

परिवहन एवं आपूर्ति श्रृंखला

- एकीकृत कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग के साथ आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएँ।
- उत्पादन समूहों के पास कृषि उत्पाद खरीद केंद्र।
- कृषि अपशिष्ट खरीद, रीसाइक्लिंग और पैकेजिंग सुविधाएँ।
- कृषि अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्र।
- फलों और सब्जियों के लिए वैक्सिंग प्लांट, पैक हाउस और कोल्ड चेन।

डेयरी

- डेयरी उत्पाद इकाइयाँ जिनमें दूध प्रसंस्करण, पनीर, चीज़ और अन्य मूल्य वर्धित उत्पाद शामिल हैं।
- उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार का निर्माण।
- ऊँट और बकरी के दूध के प्रसंस्करण की सुविधाओं के साथ मवेशी, भैंस, ऊँट और बकरी की आनुवंशिक उन्नति और बेहतर नस्लें।

ऊन

- ऊन की धुलाई, ग्रेडिंग और ऊन आधारित उद्योग समूह।
- कालीन निर्माण और ऊनी वस्त्र इकाइयाँ।

विपणन और मंडी सुविधा

- राज्य की बाज़ार समितियों में फल और सब्जियों की खरीद पर कोई बाज़ार शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क देय नहीं है।
- राज्य में प्रोसेसर/खरीदारों को पर्याप्त गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध खेती की अनुमति।
- बाज़ार क्षेत्र में खरीद केंद्र स्थापित करके राज्य में किसानों से सीधे खरीद करने के लिए विशेष लाइसेंस की अनुमति।
- प्रोसेसर को बाज़ार परिसर के बाहर प्रसंस्करण केंद्र पर सीधे खरीद करने की अनुमति।
- लाइसेंस के माध्यम से राज्य में निजी बाज़ार यार्ड स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति।
- राज्य के बाज़ार परिसर में गैर-अधिसूचित कृषि उत्पाद और खाद्य पदार्थों के व्यापार की अनुमति देकर उपयोगकर्ता शुल्क लगाया गया।

6. निवेश अनुकूल नीतियां

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) - 2024 राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और रोज़गार पैदा करने के लिए टैक्स प्रोत्साहन, सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए नीति की प्रमुख विशेषताएँ

I. एग्रो और फूड प्रोसेसिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन

- **पूंजीगत सहायता**
  - एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए पूंजी निवेश का 50%, अधिकतम ₹1.5 करोड़।
  - SC/ST उद्यमियों के स्वामित्व वाले FPO या जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में इकाइयों के लिए अतिरिक्त 5% सब्सिडी।
- **कृषि इकाइयों के लिए हरित विकास प्रोत्साहन**
  - पर्यावरणीय इंफ्रास्ट्रक्चर (ETPS), अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण के लिए 50% प्रतिपूर्ति।
  - साल के लिए कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए 100% बिजली शुल्क छूट।
  - राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत 50% सहमति शुल्क छूट।
- **कृषि उद्यमों के लिए निर्यात प्रोत्साहन**
  - पहली बार निर्यात करने वाले माल ढुलाई सब्सिडी के लिए पात्रः राज्य ICDS/ कार्गो के माध्यम से माल ढुलाई शुल्क का 25% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹25 लाख प्रति वर्ष।
- **कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ब्याज में छूट**
  - ग्रामीण पर्यटन और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अतिरिक्त 1% ब्याज सबवेंशन।
  - खादी उद्योगों के लिए अवधि 10 साल तक बढ़ाई गई।
- किसान संगठनों के लिए पात्रताः कम से कम 50 किसान सदस्यों वाले किसान उत्पादक संगठन (FPO) और किसान उत्पादक सहकारी समितियां (FPC) RIPS 2024 के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

II. इंफ्रास्ट्रक्चर और संबद्ध सहायता

- **कोल्ड चेन और भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर (पूंजी सब्सिडी)**
  - कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के लिए 20% (वार्षिक सीमा ₹15 करोड़)
  - गोदामों, साइलो और लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 25%
- **कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए लॉजिस्टिक्स सहायता**
  - राजस्थान में पंजीकृत ट्रकों के लिए ट्रैकिंग उपकरणों और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए प्रतिपूर्ति।
  - 10 लाख तक फायर डिटेक्शन सिस्टम सब्सिडी।
- मंडी शुल्क और स्टाम्प शुल्क छूट
  - 7 साल के लिए मंडी शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति
  - राज्य द्वारा अधिसूचित चरणों में 100% स्टाम्प शुल्क लाभ
- **एथेनॉल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव**
  - OMCs को सप्लाई किए गए हर लीटर एथेनॉल पर ₹1.50, जो 7 साल के लिए प्लांट और मशीनरी इन्वेस्टमेंट के 100% तक सीमित है।
- एग्री MSME के लिए स्किलिंग और ट्रेनिंग सपोर्ट
  - 6 महीने के लिए कर्मचारी ट्रेनिंग लागत का 50% रीइम्बर्समेंट। माइक्रोः ₹20,000/महीना; स्मॉलः ₹30,000/महीना; मीडियमः ₹40,000/महीना।

7. विज़न राजस्थान @ 2047

वर्ष 2047 तक राजस्थान भारत का अग्रणी कृषि शक्ति बनेगा, जिससे बेहतर उत्पादकता, किसानों की आय और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि होगी।

हम पशुधन सशक्तिकरण, सहकारिता संचालित अर्थव्यवस्थाओं और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के माध्यम से समतापूर्ण ग्रामीण विकास की परिकल्पना करते हैं। संतृप्ति आधारित जल ग्रहण हस्तक्षेप, वनरोपण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु. अनुकूलित कृषि द्वारा क्षरित भूमि का पुनर्स्थापन एवं जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म सिंचाई, कटाई उपरांत नवाचारों और स्वशासी प्रक्षेत्र प्रक्रियाओं की समन्वित प्रथाओं द्वारा राजस्थान एक आत्मनिर्भर, अनुकूलित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा, जो राष्ट्रीय समृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को संवर्धित करेगी।

प्रमुख क्षेत्र

- **जलवायु अनुकूलित कृषि:** राजस्थान की 30 प्रतिशत कृषि भूमि को जलवायु स्मार्ट तकनीकों के अन्तर्गत लाते हुए लक्षित उत्सर्जन में कमी और स्थिरता में वृद्धि सुनिश्चित करना।
- **उच्च तकनीक वाली खेती:** प्रिसिजन फार्मिंग (सटीक खेती) AI आधारित निगरानी और स्वचालित उन्नत तकनीकों से फसलों की पैदावार में 20.30 प्रतिशत की वृद्धि।
- **प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन:** सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण, AI संचालित कृषि परामर्श और स्मार्ट सिंचाई से उत्पादकता में 25 प्रतिशत तक सुधार हो सकता है।
- **कटाई उपरांत प्रबंधन और निर्यात:** कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करते हुए फसल कटाई उपरांत हानि को 25.40 प्रतिशत तक कम करना तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देना।
- **फसल विविधीकरण:** दलहन तिलहन और बागवानी को बढ़ावा देना और पारम्परिक फसलों पर निर्भरता कम करना तथा किसानों की आय में 40 प्रतिशत तक वृद्धि करना।
- **पशुधन एवं चारा अवसंरचना:** नस्ल सुधार की योजनाओं के साथ, राजस्थान भारत के दूध उत्पादन में 14.44 प्रतिशत और ऊन उत्पादन में 47.98 प्रतिशत का योगदान देता है।
- **मत्स्य पालन विकास:** 15,561 जलाशयों के साथ, मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य प्रतिवर्ष 368.50 मिलियन फिंगरलिंग्स का उत्पादन करना है, जिससे ग्रामीण आजीविका में वृद्धि होगी।
- **सहकारी ऋण सुलभता:** समावेशी विकास के लिए 55 लाख से अधिक किसानों को सहकारी बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता।
- **कृषि में महिलाएं एवं युवा:** 90 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं डेयरी फार्मिंग में प्रतिभागी, जिसके फलस्वरूप सहकारिता में भागीदारी और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा।
- **जल एवं जलवायु अनुकूलन:** राजस्थान का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 प्रतिशत गांवों को जलग्रहण परियोजना के तहत सम्मिलित करना जिससे बंजर भूमि में कमी आएगी जल की उपलब्धता में वृद्धि और कृषि उत्पादन में संवर्धन होगा।

प्रगति का बीजारोपण

- **जलवायु अनुकूलित कृषि:** सूखा- प्रतिरोधी फसलों का विस्तार, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन, जलवायु अनुकूल बीजों तक समय पर पहुंच सुनिश्चित कर राज्य के शुष्क क्षेत्रों में सतत् कृषि को बढ़ावा देना।
- **पोषण सुरक्षा एवं विविधीकरण: खाद्य** सुरक्षा एवं समग्र स्वास्थ्य को संवर्धित करने हेतु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कृषि की बढ़ती प्राथमिकता, पोषक तत्वों से भरपूर विविध फसलों को बढ़ावा देना।
- **कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन:** किसानों की आय और रोजगार में वृद्धि करने के लिए प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, ब्रांडिंग और पैकेजिंग समाधानों को बढ़ावा, राजस्थान की कृषि निर्यात और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना।
- **प्रिसिजन फार्मिंग को अपनाना:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इंटरनेट ऑफ (IOT) ड्रोन और GPS का उपयोग इनपुट के इष्टतम प्रयोग, उच्च फसल पैदावार और 270.86 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सतत् कृषि सुनिश्चित करना।
- **कृषि में सौर ऊर्जा:** पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर एग्री पंचायतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप, प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन) और कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देना।
- **जलग्रहण विकास:** 115 लाख हेक्टेयर में जल-संरक्षण कृषि पद्धतियाँ भारत के सबसे शुष्क राज्यों में से एक में जल की बर्बादी को कम करने हेतु ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों का क्रियान्वयन।
- **कटाई उपरांत अवसंरचना और यंत्रीकरण:** जलवायु-अनुकूल कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में यंत्रीकरण केंद्रों का विस्तार करना जिससे कटाई उपरांत हानि कम हो और बाजार तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित हो।
- **जैविक और प्राकृतिक खेती का संवर्धन:** 'ऑर्गेनिक राजस्थान' ब्रांड की शुरूआत, GI टैग, जैविक प्रमाणित खेतों का विस्तार तथा व्यापार सुविधा एवं अवसंरचना विकास के माध्यम से वैश्विक निर्यात को समर्थन।
- **कृषि अनुसंधान एवं नवाचार:** विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान एवं विकास (आर&डी) सहयोग को सुदृढ़ करनाए किसानों तक जलवायु अनुकूलित और उच्च उपज वाली फसलों की किस्मों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन:** जैविक खेती, यंत्रीकरण और फसल कटाई उपरांत भंडारण के लिए प्रोत्साहन, प्रशिक्षण तथा सब्सिडी प्रदान कर, राजस्थान की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और निर्यात को बढ़ावा देना।

8. ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM)

23-24-25 मई 2026 @ जयपुर

राजस्थान सरकार पूरे राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक मज़बूत कृषि और संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी विजन पर आगे बढ़ते हुए, राज्य ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM 2026) की कल्पना की है, जो एक कृषि-प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक कार्यक्रम है जो स्थायी, बाजार-संचालित और लाभदायक कृषि और संबंधित गतिविधियों को बदलने और उत्प्रेरित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

GRAM सभी प्रमुख हितधारकों - किसानों, शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों, कृषि व्यवसाय कंपनियों और नीति निर्माताओं - को एक साथ लाएगा ताकि नवीन तरीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से स्थायी कृषि और संबंधित गतिविधियों के विकास में तेजी लाई जा सके। इस मंच पर इन क्षेत्रों में उद्यमिता, साझेदारी और निवेश के अवसरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

निवेशक संवाद

17 अप्रैल : नई दिल्ली • 24 अप्रैल : अहमदाबाद • 6 मई : हैदराबाद • 8 मई : पुणे

ग्राम के उद्देश्य

- **किसान सशक्तिकरणः** किसानों को उच्च उत्पादकता और आय के लिए उन्नत तकनीकी जानकारी, नवीन प्रथाओं और उपयुक्त सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाना।
- **कृषि-नवाचारों का प्रदर्शनः** कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और उद्यमशीलता समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- **मार्केटिंग टाई-अपः** कृषि और संबंधित उद्यमों के लिए अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और खरीदारों, वितरकों और अन्य प्रमोटरों से जुड़ने के लिए संबंध स्थापित करना।
- **संयुक्त उद्यमः** पूरक शक्तियों और साझा रणनीतिक हितों वाले संगठनों के बीच सहयोग और संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरणः** संस्थानों, कंपनियों और व्यक्तिगत हितधारकों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- **अंतर्राष्ट्रीय निवेशः** घरेलू और वैश्विक फर्मों को पर्याप्त निवेश के अवसरों के लिए अपने उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- **व्यावसायिक अवसरः** प्रतिभागियों के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नए उद्यमों और विकास के रास्ते पहचानने और विकसित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना।
- **कृषि-आधारित** रिसर्च को बढ़ावा देनाः कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स पर एकेडमिक, संस्थागत और इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले रिसर्च पर विशेषज्ञों और फैसला लेने वालों के साथ चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- **कृषि और संबंधित इकोसिस्टम के लिए कॉमन प्लेटफॉर्मः** प्रदर्शनी, बातचीत और जानकारी के प्रसार के लिए पूरी कृषि वैल्यू चेन और संबंधित गतिविधियों को एक साथ लाना।

GRAM 2026 - एक नज़र में

प्रदर्शनी

प्रदर्शनी की श्रेणियां

- कृषि इनपुट और संरक्षित खेती
- सिंचाई, प्लास्टिकल्चर और सटीक खेती
- कृषि मशीनरी और संबद्ध सेवाएं
- जैविक खेती
- बागवानी
- डेयरी
- पशुधन
- मूल्य वर्धित उत्पाद
- एग्री-टेक और स्मार्ट फार्मिंग समाधान

अन्य पवेलियन

- एग्री IoT पवेलियन - ड्रोन, मोबाइल ऐप, ऑटोमेशन, AI & ML आदि
- फार्म टूरिज्म/इको टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी पवेलियन
- इन्फ्लुएंसर पवेलियन - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले मीडिया इन्फ्लुएंसर

मुख्य बातें

- कृषि, कृषि-प्रसंस्करण और पशुधन में उन्नत प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और सेवाओं का प्रदर्शन।
- शुरुआती और मध्य-चरण की एग्री-टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए घरेलू और वैश्विक कृषि व्यवसाय दर्शकों, किसानों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और निवेशकों को नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मजबूत मंच।
- अंतराष्ट्रीय भागीदारी: ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, स्पेन, अमेरिका, रशिया, वियतनाम, नीदरलैंड
- राजस्थान के किसानों और कृषि-उद्यमियों द्वारा विकसित स्वदेशी उत्पादों और समाधानों को प्रस्तुत करने का अवसर।

सम्मेलन

सम्मेलन का उद्देश्य अनुभवों का आदान-प्रदान करना, संवाद को बढ़ावा देना और किसानों की आय दोगुनी करने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार, उद्योग, शोधकर्ताओं और किसानों के लिए कार्रवाई योग्य भूमिकाओं को परिभाषित करना है।

मुख्य फोकस विषय होंगे:

- स्थिरता और जलवायु लचीलापन
- नवाचार और डिजिटल परिवर्तन
- मूल्य संवर्धन और कृषि प्रसंस्करण
- कृषि-उद्यमिता और स्टार्टअप
- सटीक, AI और डेटा-संचालित खेती

सत्र के उद्देश्य

- जलवायु-स्मार्ट, नवीन और टिकाऊ समाधानों पर चर्चा करना जो किसानों के लिए उत्पादकता, लचीलापन और संसाधन-उपयोग दक्षता को बढ़ाते हैं।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए उभरते अनुसंधान, प्रौद्योगिकियों और मानव पूंजी की जरूरतों की जांच करना। कृषि-उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना, जिसमें इनक्यूबेशन, एक्सेलेरेशन और बाजारों तक पहुंच शामिल है।
- टिकाऊ कृषि, डिजिटल कृषि और समावेशी वैल्यू चेन में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और केस स्टडी को साझा करना।
- इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाओं और निवेश के लिए सार्वजनिक-निजी और सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक साझेदारी के लिए व्यावहारिक मॉडल विकसित करना।
- महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और खेती के कामों में मेहनत कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना।

- निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए कृषि वित्तपोषण, बीमा और जोखिम प्रबंधन में नवाचार पर पुनर्विचार करना।

प्रस्तुतियाँ और पैनल चर्चाएँ

- कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और कृषि-लॉजिस्टिक्स में नए जमाने के नवीन समाधान और व्यावसायिक मॉडल।
- सूचित किसान - खेती के भविष्य, डिजिटल सलाह, जलवायु सेवाओं और बाजार की जानकारी पर सत्र।
- कृषि और खाद्य प्रणालियों में चुनौतियों और अवसरों पर वैश्विक दृष्टिकोण, जिसमें व्यापार और स्थिरता परिवर्तन शामिल हैं।
- प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स और आधुनिक खुदरा बिक्री के माध्यम से किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने पर वैल्यू-चेन सत्र।
- लिंग-उत्तरदायी टेक्नोलॉजी, संपत्ति, सेवाओं और कौशल तक पहुंच के माध्यम से कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने पर संवाद।
- नए कृषि उद्यमों के लिए इनक्यूबेशन और स्केलिंग सहायता, जिसमें स्टार्टअप पिच और निवेशक बातचीत शामिल है।
- बाजार-संचालित नवाचार, निवेश-अनुकूल विनियमन और जलवायु-स्मार्ट प्रोत्साहन को सक्षम करने के लिए नीति गोलमेज।
- अगली पीढ़ी के कृषि समाधानों के लिए अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के बीच अनुसंधान और विकास और साझेदारी के अवसर।
- कृषि और ग्रामीण आजीविका को बदलने के लिए जलवायु-स्मार्ट, नवीन और टिकाऊ तरीकों पर विषयगत चर्चा।

इवेंट की मुख्य बातें

- **वीडियो एरिना:** एक ऑडियो-विज़ुअल ज़ोन जहाँ ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स आकर्षक वीडियो और इमेज के ज़रिए खेती के बेहतरीन तरीकों, प्रोडक्शन सेटअप और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को दिखा सकते हैं।
- **ग्रामीण मॉल:** इनोवेटिव कृषि उत्पादों को दिखाने और बेचने के लिए एक डायनामिक मार्केटप्लेस, जिसे आधुनिक एग्री-मॉल की तरह ग्रामीण खरीदारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **एग्री-एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप कैंप:** उभरते एग्री-एंटरप्रेन्योर्स के लिए इनक्यूबेशन और सपोर्ट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बिज़नेस मॉडल पर फोकस करते हुए मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस और रिसोर्स प्रदान करता है। एग्री-स्टार्टअप में निवेश आकर्षित करने पर विशेष ज़ोर।
- **एग्री क्लीनिक (किसान गोष्ठी):** किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सीधे सलाह-मशविरे के लिए प्लेटफॉर्म। विशेषज्ञ खास फसलों और तरीकों पर खास सलाह देते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छे समाधान पहचानने में मदद मिलती है।
- **लाइव डेमोंस्ट्रेशनः** अत्याधुनिक मशीनों और फसल कटाई के बाद की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन। इसमें राजस्थान के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के लिए विकसित इनोवेटिव समाधानों के डेमोंस्ट्रेशन शामिल हैं।
- **क्षमता विकास कार्यक्रमः** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रमुख लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो विस्तार और लंबे समय तक विकास चाहते हैं।
- **पुरस्कारः** कृषि में उल्लेखनीय इनोवेशन और उपलब्धियों के लिए सम्मान।

कौन - कौन भाग ले सकते हैं?

- केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी
- राष्ट्रीय और वैश्विक कृषि अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ
- वित्तीय संगठनों (बैंक, नाबार्ड, सिडबी) के प्रतिनिधि
- कृषि विश्वविद्यालयों और मैनेजमेंट कॉलेजों के शिक्षाविद
- एग्री-बिज़नेस और खाद्य कंपनियाँ (भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय)
- प्रगतिशील किसान और किसान संगठन
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स (कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स)
- विकास एजेंसियाँ (कमोडिटी बोर्ड, APEDA, FAO, IFA आदि)

GRAM 2026 में क्यों शामिल हों?

- राजस्थान के फलते-फूलते कृषि क्षेत्र में नए निवेश के अवसर खोजें।
- निवेश करके और पार्टनरशिप बनाकर राज्य के विकास में हिस्सा लें।
- राजस्थान की कृषि और संबंधित उद्योगों में उभरते रुझानों के बारे में जानकारी हासिल करें।
- वर्तमान और भविष्य की कृषि पहलों पर सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करें।
- तीन दिनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्री-बिज़नेस के हितधारकों के व्यापक समूह के साथ नेटवर्क बनाएं।
- क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों और समाधानों पर अग्रणी उद्योग व्यवसायों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करें।
- नवीनतम कृषि-इनोवेशन और तरीकों के सीधे डेमोंस्ट्रेशन का अनुभव करें।
- व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए समर्पित मंचों पर अपना मामला पेश करें।
- जाने-माने भारतीय और वैश्विक एग्रीबिज़नेस लीडर्स से जुड़ें।

9. प्रमुख सम्पर्क

प्रदर्शनी

श्री अक्षय जैन

उप निदेशक, FICCI

मोबाइल : +91 704 252 5557

ईमेल : akshay.jain@ficci.com

कॉन्फ्रेंस

सुश्री नेहा माथुर

सलाहकार, कृषि

मोबाइल : +91 963 669 3100

ईमेल : neha.mathur@ficci.com

श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत

अतिरिक्त निदेशक, कृषि (Extension)

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान सरकार

पंत कृषि भवन, जनपथ, सी-स्कीम, जयपुर 302005

मोबाइल : +91 141 222 7849 I ईमेल : adldir.ext.agri@rajasthan.gov.in

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM)

23-24-25 मई 2026 @ जयपुर

आयोजक

कृषि विभाग राजस्थान DOA

कृषि विभाग
राजस्थान सरकार

समिट पार्टनर

FICCI 100 YEARS OF BUILDING TOMORROW

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ
कॉमर्स और इंडस्ट्री

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) 2026

gram-rajasthan.in

कृषि
विभाग
राजस्थान DOA